

इंटरनेट की स्वतंत्रता

प्रलिस के लिये:

[नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, अनुच्छेद 370, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144](#)।

मेन्स के लिये:

इंटरनेट स्वतंत्रता, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

लगातार पाँच वर्षों से भारत इंटरनेट प्रतिबंध लगाने वाले देशों की वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, **वर्ष 2016 और वर्ष 2022 के बीच** दुनिया में दर्ज किये गए सभी ब्लैकआउट में से लगभग 60% भारत में हुए हैं।

- पछिले दशक में राज्य द्वारा लगाए गए शटडाउन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरे का हवाला दिया है। हालाँकि अधिकार समूहों ने तर्क दिया है कि ये शटडाउन अदालत के निर्देशों का भी उल्लंघन करते हैं।

भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख रुझान क्या हैं?

- इंटरनेट शटडाउन के उदाहरण:**
 - सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (Software Freedom Law Centre- SFLC) द्वारा एकत्र किये गए आँकड़ों के अनुसार, **भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2014 और 31 दिसंबर, 2023 के बीच कुल 780 शटडाउन** लगाए।
 - [नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019](#) में [अनुच्छेद 370](#) को नरिसूत करने और [कृषि विधियक 2020](#) प्रस्तुत करने के खिलाफ वरिध प्रदर्शन हुआ।
 - भारत का इंटरनेट प्रतिबंध **वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए कुल नुकसान के 70% से अधिक** के लिये ज़िम्मेदार रहा।
 - भारत ने वर्ष 2023 में 7,000 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रखा।
 - क्षेत्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर में पछिले 12 वर्षों में सबसे अधिक 433 शटडाउन देखे गए।
 - जातीय झड़पों के बीच वर्ष 2023 में सबसे लंबा ब्लैकआउट मई से दिसंबर तक मणपुरि में हुआ।
 - SFLC डेटा के अनुसार, वर्ष 2015 और 2022 के बीच 55,000 से अधिक वेबसाइटें ब्लॉक की गईं।
 - सेंसर की गई सामग्री का सबसे बड़ा हिससा [IT अधिनियम की धारा 69A](#) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किये गए थे।
 - [गैर-कानूनी गतिविधियाँ \(रोकथाम\) अधिनियम](#) के तहत प्रतिबंधित संगठनों के लिके के कारण URL ब्लॉक कर दिये गए थे।
- वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता:**
 - [फ्रीडम हाउस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार](#), वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 13वें वर्ष गरिवट आई है और 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकारों के लिये माहौल खराब हो गया है।
 - पछिले तीन वर्षों में भारत की रैंकिंग इसी बेंचमार्क के आस-पास रही है।
 - वर्ष 2016-2017 में भारत ने 59 अंक और वर्ष 2023 में 50 हासलि किये थे।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) जो दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी नलिंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नयिम, 2017 के साथ पठति है:**
 - ये नयिम संघ या राज्य के गृह सचवि को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में कसि भी टेलीग्राफ या तार सेवा

(इंटरनेट सहित) को नलिंबति करने का आदेश देने की अनुमति देते हैं।

- ऐसे आदेश की एक समिति द्वारा पाँच दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिये और यह एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधितक जारी नहीं रह सकता। किसी अत्यावश्यक स्थिति में, संघ या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है।
- हालाँकि कानून यह परभाषति नहीं करता है कि आपातकालीन या सुरक्षा मुद्दा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक [अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले, 2020](#) में दोहराया कि इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और अनश्चित काल तक चलने वाला शटडाउन असंवैधानिक है।

■ [दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144](#):

- यह धारा एक ज़िला मजिस्ट्रेट, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी भी उपद्रव या गड़बड़ी को रोकने या प्रतर्बिधति करने के लिये आदेश जारी करने का अधिकार देती है।
- ऐसे आदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में एक नरिदष्टि अवधि के लिये इंटरनेट सेवाओं का नलिंबन शामिल हो सकता है।

इंटरनेट शटडाउन के संबंध में क्या तर्क हैं?

■ घृणा वाक् / हेट स्पीच और गलत सूचना को रोकता है:

- इंटरनेट शटडाउन से [घृणा वाक्](#) और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है जो हिसा तथा दंगे भड़का सकते हैं।
- उदाहरण के लिये, सरकार ने गलत सूचना से नपिटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिये [गणतंत्र दविस पर कसिानों के वरिध के बाद दलिली NCR में इंटरनेट बंद करने की घोषणा](#) की।

■ किसी भी राष्ट्र-वरिधी गतविधियों को रोकता है:

- इंटरनेट शटडाउन से सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बाधति करने वाले वरिध प्रदर्शनों के आयोजन एवं लामबंदी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
- उदाहरण के लिये, सरकार ने किसी भी राष्ट्र-वरिधी गतविधियों और अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिये [अनुच्छेद 370](#) को नरिस्त करने के बाद [कश्मीर एवं देश के अन्य हिसिाँ में इंटरनेट शटडाउन](#) लगा दिया।

■ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है:

- इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बाह्य खतरों तथा [साइबर अटैक](#) से बचाने में मदद कर सकता है।
- उदाहरण के लिये, सरकार ने [चीन के साथ गतरिध](#) के दौरान किसी भी जासूसी या उपद्रव को रोकने के लिये कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को नलिंबति कर दिया था।

■ उपभोग से आपतजनिक सामग्री पर अंकुश:

- इंटरनेट शटडाउन से उस कंटेंट के वरिण और उपभोग को नरिंतरति करने में मदद मिल सकती है जो कुछ समूहों या व्यक्तियों के लिये हानिकारक या आपतजनिक हो सकती है।
- उदाहरण के लिये, सरकार आपतजनिक छवियों या वीडियो के प्रसार को रोकने के लिये [कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रयोग को बंद](#) कर देती है।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधति चतिाँ क्या हैं?

■ अधिकारों का उल्लंघन:

- इंटरनेट शटडाउन [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) और [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
 - वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है- सर्वोच्च न्यायालय में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला, 2020।
 - इंटरनेट शटडाउन [सूचना के अधिकार](#) का भी उल्लंघन करता है जसिे [राज नारायण बनाम यूपी राज्य \(वर्ष 1975\)](#) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा [अनुच्छेद 19](#) के तहत एक मौलिक अधिकार घोषति कया गया है।
 - इंटरनेट शटडाउन [इंटरनेट के अधिकार](#) का भी उल्लंघन करता है जसिे केरल उच्च न्यायालय ने [फहीमा शरीन बनाम केरल राज्य मामले](#) में [अनुच्छेद 21](#) के तहत एक मौलिक अधिकार घोषति कया था।

■ जवाबदेहति का अभाव:

- शटडाउन प्रायः [सपष्ट कानूनी ढाँचे](#) अथवा नरिक्षण तंत्र के बिना लागू कयि जाते हैं जसिसे इंटरनेट पहुँच पर मनमाना और अनुपातहीन प्रतर्बिध संभव होता है।
- संबद्ध वषिय में जवाबदेहति तंत्र का अभाव अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग के जोखमि को बढ़ा देता है जो प्रभावति होने वाले व्यक्तियों के लिये पर्याप्त औचितिय अथवा दायतिव के बिना शटडाउन लगा सकते हैं।

■ आर्थिक व्यवधान:

- तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के अतरिकित [इंटरनेट शटडाउन से संबंधति महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव](#) भी होते हैं। ऑनलाइन वाणजिय, संचार और वरितीय लेन-देन में होने वाले व्यवधान से व्यवसाय संचालन बाधति होता है, आर्थिक वकिस तथा नविश प्रभावति होता है जसिसे अंततः दीर्घकालिक वकिस अत्यधिक प्रभावति हो सकता है।
 - Top10VPN के अनुसार, इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारत को 2,091 करोड़ रुपए (\$255.2 मिलियन) का नुकसान हुआ।

■ सामाजिक व्यवधान:

- इंटरनेट शटडाउन [संचार नेटवर्क](#) को बाधति करके, [महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच](#) में बाधा डालकर और व्यक्तियों को उनके समुदायों से अलग कर सामाजिक व्यवस्था को बाधति करता है। इसके परणामस्वरूप सामाजिक एकजुटता प्रभावति हो सकती है क्योंकि इस दौरान लोग

प्रभावी ढंग से संपर्क करने, संगठित अथवा एकजुट होने में असमर्थ होते हैं जिससे उनमें अलगाव और वरिग की भावना जागृत हो सकती है।

आगे की राह

- सरकारी अधिकारियों को **अनुराधा भसीन मामले (2020)** में **सर्वोच्च नयायालय** द्वारा दिये गए नरिदेशों का अनुपालन करना चाहिये। सर्वोच्च नयायालय द्वारा जारी किये गए दशिया-नरिदेश नमिनलखिति थे:
 - नलिंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिये कयि जा सकता है।
 - नलिंबन नयिमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को रोकने के संबंध में जारी कयि गए कसिी भी प्रकार के आदेश में आनुपातकितता के सदिधांत का अनुपालन सुनशिचति करते हुए उसे आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
 - नलिंबन नयिमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को रोकने के लिये जारी कयि गया कसिी भी प्रकार का आदेश **न्यायकि समीकषा के अधीन** है।
- इंटरनेट शटडाउन को नयित्त्रति करने वाले वधिकि और वनियामक ढाँचे को सुदृढ़ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार उनका उपयोग केवल **अंतमि उपाय** के रूप में कयि जाना सुनशिचति कयि जाना चाहिये।
 - सरकार को **तार अधनियिम (Telegraph Act) और उसके नयिमों** में संशोधन करना चाहिये, जो अद्यतन तथा सुस्पष्ट नहीं हैं एवं इनमें संवैधानकि व मानवाधिकार मानकों का अनुपालन नहििति नहीं है।
- सरकार को **कानून-व्यवस्था में व्यावधान**, सांप्रदायकि इसिा, आतंकवादी हमलों, परीकषाओं और राजनीतकि अस्थरिताका **समाधान करने के लिये अन्य अल्प हस्तकषेप वाले उपायों पर वचिार करना चाहिये** जसिमें वशिषिट वेबसाइटों अथवा संबंधति सामगरी तक पहुँच अवरुद्ध करना, चेतावनी अथवा सलाह जारी करना, नागरकि समाज तथा मीडिया के साथ जुड़ना अथवा अधकि सुरकषा बलों की तैनाती करना शामिल है।

प्रश्न: इंटरनेट शटडाउन से संबंधति सांवाधिकि और मानवाधिकार संबंधी चतिाओं का मूल्यांकन कीजयि तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उनका समाधान करने हेतु उपायों का वविरण दीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतरभूत भाग के रूप में संरकषति कयि जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपरयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दरेि राज्य की नीतके नदिशक तत्त्व
- अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न. आप 'वाक् और अभवियक्ता स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फलिमें अभवियक्ताके अन्य रूपों से तनकि भनिन स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजयि। (2014)